श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मेहता जी ने बड़ी तारीफ की है क्योंकि मेहता जी वहां के हैं और वहां काम भी करते हैं। उन का पक्ष जो भी हो लेकिन यह बात सही है कि जिस तरह की धांधली बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी में हो रही है...

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो हो गई है। अगर आप को कोई नई बात पूछनी है, तो पूछिये।

श्री शिव प्रसाद साहू : मान्यवर, वही तो मैं करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई नई बात हो, तो पूछिये।

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं। कि वहां पर बहाली स्थानीय लोगों की नहीं की जा रही है और मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है और शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर मंत्री महोदय ध्यान दें और उस कालेज को रांची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत डाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इरेलेवेन्ट, आप बैठ जाइए। क्वेश्चन नं० 227।

वादीनार बंदरगाह का विकास

*227. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ की खाड़ी में वादीनार बंदरगाह का विकास कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) वादीनार बंदरगाह में "कार्गो" और "बल्क कार्गो" सुविधाएं प्रदान करने पर कितना व्यय होने की संभावना है और इस संबंध में क्या प्रबंध किए गए हैं ; और

(ग) क्या इस बंदरगाह में यह कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जायेगा, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि लगभग समाप्त होने वाली है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z. R. ANSARI): (a) At the time of the formulation of the 6th Plan 1980-85) a provision for development of Vadinar Port with a taken outlay of Rs. 100 lakhs was incorporated in the Plan, on the basis of preliminary justification only. Such Schemes are, however, taken up only after detailed analysis is made and their justification and viability established. Further investigations have not yet established the full justification for this Scheme.

(b) Nill.

(c) Does not arise.

श्री नरसिंह मकवाना : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह अध्ययन का काम कब शुरू हुआ, किस को सौंपा गया और यह अध्ययन कब तक पूरा हो जाएगा? इस के लिए मंत्री जी क्या कोई समय बताएंगे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने कंसलटेन्ट से प्रोपोजेल्स मांगे और अब वे आ गये हैं और कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने मेसर्स होव एण्ड कम्पनी का लो-अस्ट टेन्डर होने की वजह से उस को एक्सेप्ट कर लिया है। फार्मल प्रोपोजल

अभी कांडला पोर्ट ट्रस्ट का गवर्नमेंट के पास नहीं आया है और जैसे ही प्रोपोजल आ जाएगा और उस की क्लियरेन्स हो जाती है, It will take three to four months to get the study done.

श्री नरसिंह मकवाना : मंत्री जी का जवाब बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । इसलिए मैं फिर उन से पूछना चाहता हूं कि यह जो अध्ययन की रिपोर्ट थी, वह क्या है, वह कब शुरू किया, किस की मारफत शुरू किया और उस के अन्दर क्या सुझाव थे ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : पहला तो छठी पंचवर्षीय योजना में एक मल्टी-कोमोडिटी बल्क कार्गो के लिए बर्थ का प्रोपोज़ल था और यह था कि पंचवर्षी योजना के आखरी साल में मल्टी कोमोडिटी बल्क कार्गो की बर्थ लग जाए । फिर उस के बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गये, तो एक प्रोपोजल आया कि एक फुलफुलेज्ड पोर्ट वादीनार में बनाया जाए । तो सारे ब्यूज गुजरात गवर्नमेंट के और कांडला पोर्ट ट्रस्ट के आए थे लेकिन आखरी बात जो तय हुई वह यह थी कि एक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली जाए और फिजीबिलिटी रिपोर्ट में ये सारे क्वेश्चन आए कि एक पूरा पोर्ट होना चाहिए या एक बर्थ होनी चाहिए या सिर्फ एक जेटी होनी चाहिए । क्या चीज बने और फिजीबिलिटी रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद पूरा प्लान हमारे सामने आ जाए और उसी के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने होव एंड कम्पनी को सलेक्ट किया । फिजीबिलिटि रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद, जो भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उस के बाद according to the report of the consultants, action will be taken.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें नोटिस आफिस से क्वेश्चन का जो जवाब मिला है उसमें लिखा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में सौ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, ऐसा बतलाया गया है । माननीय मंत्री बोल रहे हैं एक करोड़ का किया है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैंने एक करोड़ का कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : सुनने में कुछ गड़बड़ी हो गई है ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : गुजरात गवर्नमेंट ने कांडला पोर्ट के बारे में एक ट्रेफिक सर्वे कराया था । उसके अनुसार एक मिलियन टन का ट्रेफिक इस पोर्ट को मिलने वाला है । उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया । क्या गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा सर्वे कराया था और उसने आपको यह बताया था कि 15 मीटर तक कि यहां गहराई है । वहां फर्टिलाइजर कम्पनी फर्टिलाइजर प्लांट भी रखना चाहती है । उद्योग की दृष्टि से कच्चा माल भी इस पोर्ट के द्वारा आयेगा । इसका भी काफी कार्गो ट्रेफिक आपको मिलने वाला है । इस सब को देखते हुए इस पोर्ट को छठी पंचवर्षीय योजना में अमल में लाया जाए, क्या इसके बारे में तीव्र गति से सोचा जाएगा ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हमें गुजरात गवर्नमेंट से इख्तिलाफ है । चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने जो लेटर लिखे हैं कि कांडला पोर्ट में इतना ट्रेफिक होगा, वे फिगर्स एग्जेजरेटिड लगते हैं । एक मिलियन टन का ट्रेफिक वहां नहीं है । कांडला पोर्ट

ट्रस्ट ने जो स्टडी की है उससे नहीं लगता है कि वहां इतना कार्गो ट्रैफिक मिल जाएगा। इस सारे केस को स्टडी करने के लिए एक कंसलटेंट अपोइंट करने का फैसला किया गया है। कंसलटेंट के मुकर्रर होने के बाद, और उसके तमाम मसले पर गौर करने के बाद जो चीज सामने आयेगी, उस पर गवर्नमेंट अपना व्यू बनायेगा। कंसलटेंट अपोइंट होने के बाद चार-पांच महीने का वक्त लग जायेगा उसकी रिपोर्ट आने तक। उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना व्यू बनायेगी कि क्या किया जाए। जहां तक हमारा सवाल है हमने सिक्सथ फाइव इयर प्लान में एक करोड़ रुपया इस काम के लिए रख दिया है।

रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठे छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं का गुम हो जाना

*229. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे हजारों छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं गुम हो गई हैं, जो रेल सेवा आयोग, इलाहबाद द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठे थे ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) फरवरी, 1981 में रेल सेवा आयोग, इलाहबाद द्वारा आयोजित गैर-तकनीकी श्रेणियों के उम्मीदवारों की भर्ती संबंधी परीक्षा का परिणाम घोषित करने तथा कुछ छात्रों का साक्षात्कार लेने के बाद कितने छात्रों का चयन किया गया था और शेष छात्रों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की जा रही है तथा क्या इस संबंध में वर्तमान चेयरमैन का घेराव किया गया था ; और

(ङ) क्या वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान परीक्षा और साक्षात्कारों का आयोजन दोषपूर्ण ढंग से किया गया है तथा यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है और केवल कुछ उम्मीदवारों का चयन करने का क्या औचित्य है ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (A.B A. GHANI KHAN CHAUDHURI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) In respect of written Examination conducted by Railway Service Commission, Allahabad in February, 1982, it was found that answer sheets of about 80,000 candidates had been missing. A supplementary examination has already been held for these candidates on 27.11.1983.

(b) The matter is part of a vigilance enquiry which is in progress.

(c) The result of the examination held in 1981 has already been notified for 579 candidates and for the remaining the matter is under examination with the Vigilance Department in the Ministry of Railways, since some malpracticas are suspected.

(d) and (e) As indicated against (c) above, the matter is under investigation by Vigilance Department of the Ministry of Railways. The Chairman had been 'gheraoed' at times by the candidates (whose names did not appear in the list notified) acting in conjunction with some outsiders. Neither the written examina-